

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर
आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-6698/2006

संदीप प्रभाकर बनाम राजस्थान राज्य
दिनांक:16.11.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री पंकज गुप्ता, अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से
श्री आर पी कुलदीप, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य
श्री सत्य नारायण शर्मा, अनुसंधान अधिकारी व्यक्तिशः उपस्थित

--

अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रथम सूचना संख्या-201/2006 पुलिस थाना- मोती इंगरी, जयपुर शहर अपराध अन्तर्गत धारा- 147, 323, 341, 382 भा.दं.सं.के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।

इस पर अभियुक्त- प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी तथा दौरान बहस प्रस्तुत दस्तावेज / केस डायरी का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से तर्क दिया गया है कि आई सी आई सी आई बैंक वाहन पर फायनेंस करती है तथा एग्रीमेंट में शर्तें होती हैं एवं शर्तों के उल्लंघन पर आई सी आई सी आई बैंक हायर पर्चेज वाहन का पुनः कब्जा प्राप्त कर सकती है। इस मामले में परिवादी ने वाहन आई सी आई सी आई बैंक से हायर पर्चेज पर लिया था, जिसके द्वारा कई किश्तों की चूक की गयी, जिस पर बैंक द्वारा अनेकों नोटिस दिये गये तथा परिवादी ने नोटिस दिये जाने के बावजूद भी किश्ते नहीं चुकायी जिस पर आई सी आई सी आई बैंक के नोटिस के बाद प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा उक्त वाहन को कब्जे में लिया गया। उनका यह भी तर्क रहा है कि इस हेतु आई सी आई सी आई बैंक व अभियुक्त-प्रार्थी के मध्य एक एग्रीमेंट भी हो रहा है। उनका यह भी तर्क है कि उक्त वाहन को वैशाली नगर थाना इलाके से कब्जे में लिया गया था, जिसके कब्जे में लेने के उपरान्त उसी दिन वैशाली नगर थाना को लिखित में सूचना दे दी गयी थी। तत्पश्चात् दूसरे दिन यह एफ आई आर मोती इंगरी थाना में दर्ज करवायी गयी है जबकि मोती इंगरी थाने में तो उक्त वाहन का कब्जा ही नहीं लिया गया था। उनका यह भी तर्क रहा है कि उक्त वाहन की बकाया किश्ते

परिवादी नरपत सिंह द्वारा चुका दिये जाने पर आई सी आई सी आई बैंक द्वारा उक्त वाहन नरपत सिंह को दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं की गयी तथा सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त वाहन परिवादी को सुपुर्दगी पर दे दिया गया। अपने तर्क के समर्थन में दा मैनेजिंग डाइरेक्टर ऑरिक्स ऑटो फाइनेंस इण्डिया लि. बनाम जगमिन्द्र सिंह व अन्य 2006(1) सुप्रिम 708 व चरण जीत सिंह चढ्ढा व अन्य बनाम सुधीर मेहरा ए आई आर 2001 एस सी पेज- 3721 का अवलम्बन लिया है।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा तर्क दिया कि जबरन वाहन का कब्जा मोती इंगरी थाना क्षेत्र में ले लिया गया तथा वाहन चालक के साथ मारपीट की गयी ,जिसकी रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी थी।

हमने उभय पक्ष के तर्कों एवं दौरान बहस प्रस्तुत समग्र प्रलेखीय सामग्री पर विचार किया।

केस डायरी में एकत्रित की गयी सामग्री व दौरान बहस प्रस्तुत की गयी अन्य सामग्री को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि विवादित वाहन को परिवादी ने आई सी आई सी आई बैंक से लोन लेकर हायर पर्चेज पर प्राप्त किया था तथा उसकी किश्ते अदा न करने के नोटिस आई सी आई सी आई बैंक द्वारा परिवादी को दिये गये। आई सी आई सी आई बैंक व अभियुक्त-प्रार्थी के मध्य हुए एग्रीमेंट की कॉपी प्रस्तुत हुई है , जिससे भी यह प्रदर्शित हो रहा है कि आई सी आई सी आई बैंक की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में हायर पर्चेज वाहन का पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए अभियुक्त-प्रार्थी को अधिकृत कर रखा है उक्त वाहन का कब्जा लेने के उपरान्त उसकी सूचना तुरन्त वैशाली नगर थाना को दिया जाना बताया गया है।

इस प्रक्रम पर इस मामले के गुणावगुण पर विशेष विवेचन किया जाना उपयुक्त नहीं है किन्तु अपराध की प्रकृति व अभियुक्त की इस अपराध में बतायी गयी लिप्तता, उभय पक्ष के तर्कों व प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मेरी राय में प्रार्थी को धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता का लाभ दिया जाकर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अभियुक्त- प्रार्थी का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी संदीप प्रभाकर पुत्र श्री धर्मपाल प्रभाकर निवासी- 147, गिरनार कॉलोनी, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर को पुलिस थाना-मोती इंगरी, जयपुर शहर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 201/206-में गिरफ्तार

किया जावे तो उसे अन्वेषण अधिकारी/ गिरफ्तारी अधिकारी/ एस.एच.ओ. की सन्तुष्टि पर प्रार्थी द्वारा रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का स्वयं का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व रुपये 5,000/- -- 5,000/-(पांच-पांच हजार रुपये मात्र) की दो प्रतिभूति पत्र प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे:

1. यह कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों के उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. यह कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. यह कि प्रार्थी न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
4. यह कि प्रार्थी भविष्य में इस तरह की प्रकृति के अपराध में लिप्त नहीं होगा।

(न्या० जितेन्द्र राय गोयल)